भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
आर्थिक कार्य विभाग
लोकसभा
अतारांकित प्रश्न सं. 1001
(जिसका उत्तर सोमवार दिनांक 10 फरवरी, 2025/21 माघ,1946 (शक) को दिया जाना है।)

जलवायु वित्त वर्गीकरण

1001. श्री विशालदादा प्रकाशबापू पाटीलः

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) केन्द्रीय बजट 2024-25 में घोषित देश के जलवायु वित्त वर्गीकरण का ब्यौरा और वर्तमान स्थिति क्या है;

(ख) आर्थिक गतिविधियों को हरित या टिकाऊ रूप में वर्गीकृत करने के लिए उपयोग किए जाने वाले मानदंड और मैट्रिक्स क्या हैं और क्या यह अंतर्राष्ट्रीय मानकों और सर्वोत्तम प्रथाओं के अनुरूप हैं;

(ग) वर्गीकरण के प्रारंभिक चरण में किन क्षेत्रों को प्राथमिकता दी जा रही हैं;

(घ) सरकार द्वारा हरित वर्गीकरण को अपनाने को प्रोत्साहित करने और वित्तीय संस्थानों की निर्णय लेने की प्रक्रियाओं में जलवायु संबंधी जोखिमों को एकीकृत करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ङ) ग्रीनवाशिंग को रोकने और हरित वर्गीकरण की अखंडता सुनिश्चित करने के लिए सुरक्षा उपाय क्या हैं?

उत्तर
वित्त राज्य मंत्री (श्री पंकज चौधरी)

(क) और (ड़): जुलाई 2024 में जलवायु वित्त के लिए वर्गीकरण के बारे में बजट घोषणा के अनुरूप, विभाग ने वर्गीकरण संबंधी कार्य पर चर्चा, विचार-विमर्श करने और मार्गदर्शन के लिए कई हितधारकों को शामिल करते हुए क्षेत्रीय तकनीकी समितियों (टीसी) का गठन किया है। यह वर्गीकरण देश की जलवायु प्रतिबद्धताओं को पूरा करने और हरित परिवर्तन के लक्ष्य की प्राप्ति में सहयोग करेगा तथा ग्रीनवाशिंग को रोकेगा। भारतीय रिजर्व बैंक ने जलवायु जोखिमों के प्रबंधन में प्रमुख अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की तैयारी और प्रगति का आकलन करने के लिए सर्वेक्षण सहित कई उपाय किए हैं, और हरित गतिविधियों/परियोजनाओं हेतु ऋण प्रवाह बढ़ाने के लिए ग्रीन डिपॉजिट स्वीकार करने संबंधी फ्रेमवर्क भी जारी किया है। इसके अतिरिक्त, सेबी ने सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग और ईएसजी-संबंधी अनिवार्य प्रकटीकरण की शुरुआत की है, जिसमें बाजार पूंजीकरण के हिसाब से 1000 शीर्ष सूचीबद्ध कंपनियों को कवर किया गया है।

****